(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कु० सैलजा): (क) 1965 में इसके प्रारम्भ से ही भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला ने अभी तक 194 खण्ड प्रकाशित किए हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(I) विनिबन्ध	—	95
(II) सेमिनारों की कार्रवाई	—	45
(III) अतिथि प्रोफेसरों द्वारा लेक्चर	—	23
(IV) प्रासंगिक पेपर	—	19
(V) पुनः मुद्रण	—	12

इस समय 12 पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं।

(ख) पिछले छः वर्षों के दौरान अध्येताओं द्वारा आरम्भ की गई शोध परियोजनाओं का ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है [देखिए परिशिष्ट 173, अनुपत्र सं० 126]

(ग) व (घ) संस्थान ने 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय अध्येता के रूप में अपनी पसंद के विषय पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हिन्दी लेखक डा० भीष्म साहनी को आमंत्रित किया था। डा० प्रेम सिंह को "स्वतंत्रोत्तर हिन्दी व बंगला उपन्यासों में क्रांति व इसकी राजनीति के विचार" पर कार्य करने हेतु तीन वर्षों की अवधि के लिए शोध अध्येतावृति दी गई थी।

Functioning of UGC Regional Offices

5692. SHRI GUNDAPPA KORWAR: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether all the regional Offices of the University Grants Commission have started functioning; and

(b) *if not, the reasons therefor?*

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) and (b) According to the information furnished by the University Grants Commission, the Regional Offices of UGC at Hyderabad, Pune, Bhopal and Ghaziabad have started functioning. The Regional Offices at Guwahati and Calcutta are likely to become functional soon.

रोजगारोन्मुख शिक्षा

5693. **श्री अनन्त राम जायसवाल:**
श्री सत्य प्रकाश मालवीय:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्कूल स्तर पर कम्प्यूटर की आधारभूत जानकारी सहित रोजगारोन्मुख शिक्षा संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्रियान्वयन और रोजगारोन्मुख शिक्षा पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी और उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन तथा पूरा होने की समय अवधि क्या होगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कु० सैलजा): (क) और (ख) शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की दृष्टि से, भारत सरकार ने फरवरी 1988 में माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरंभ की थी। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1995-96 के लिए 82.00 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई है। यह एक वर्तमान योजना है तथा इस समय संपूर्ण देश के 6280 स्कूलों में 18055 व्यावसायिक कक्षाएं अनुमोदित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 150 विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं जिसमें कम्प्यूटर पाठ्यक्रम भी शामिल हैं।

इसके अलावा, 1984-85 में आरंभ की गई "स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन" (क्लास) नामक एक अग्रगामी योजना को वर्ष 1993-94 में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में संशोधित कर दिया गया था। इस संशोधित योजना के अन्तर्गत चुनिन्दा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा XI तथा XII के सभी छात्रों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा में अध्ययन अनिवार्य

होगा। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 3265 स्कूल पहले ही शामिल किए जा चुके हैं। चालू वित्त वर्ष में अतिरिक्त 500 स्कूलों को शामिल करने के लिए 47 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई है।

Dutch Assisted programme for Women

5694. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether a National Commission for women has been set up if so, the specific tasks assigned to it;

(b) what is the present constitution of the Commission; and

(c) whether a Dutch assisted programme for women's empowerment through education was currently in operation in the country; if so, the details of its activities carried out under the programme in Uttar Pradesh in general and U.P. Hill districts in particular?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT THE DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SMT. BASAVARAJESWARI): (a) Yes, Sir. The specific tasks of the National Commission for Women has been given in Section 10 of the National Commission for Women Act, 1990.

(b) The National Commission for Women comprises of Smt. Ganga Potai, Member and Smt. Annie Prasad, Member Secretary.

(c) Yes, Sir. Mahila Samakhya programme (Education for Women's Equality) is a 100% Dutch assisted project. The programme, launched in 1989, is spread over 15 districts of Uttar Pradesh, Karnataka, Gujarat and Andhra Pradesh. Mahila Samakhya is a women's empowerment project which does not aim at service delivery but seeks to bring about a change in women's perception about themselves and that of society in regard to women's 'traditional roles' It endeavours to cr[illegible] an environment for women to seek [illegible]vledge and information in order to [illegible]ke informed choices and create circumstances in which women can learn at their pace and rhythm. The centrality of education in the struggle to achieve equality is an important focus of Mahila Samakhya.

At present Mahila Samakhya is being implemented in four districts of Uttar Pradesh covering 521 villages. The districts are: Tehri, Saharanpur, Varanasi and Banda. In Uttar Pradesh the Mahila Samakhya programme has focussed on issues like drinking water, mobilization of rural women around issues of violence, environment, literacy, wages and health in the districts.

Courses taught by North Eastern Regional Institute of Science and Technology

5695. SHRI VIRENDRA KATARIA: SHRI GUNDAPPA KORWAR:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of degree courses taught in the North Eastern Regional Institute of Science and Technology alongwith the number of students admitted at present and how many students have since passed degree examination of this Institute during the last two years;

(b) whether budgetary allocation for the year 1995-96 of the North Eastern Regional Institute of Science and Technology has been reduced and if so, the details thereof and the reasons therefor;

(c) whether students from other states are also admitted in these courses and if not, the reasons thereof for; and

(d) the salient features of the Expert Committee report which was appointed to look into the academic and other development issues of the Institute and the decision taken by the Government thereon?